ए-45011/04/2023-समन्वय.II
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)
***

नई दिल्ली, 16 फ़रवरी, 2024

कार्यालय ज्ञापन

अधोहस्ताक्षरी को दिसंबर, 2023 के माह के लिए आर्थिक कार्य विभाग के संबंध में महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों पर मासिक सारांश के अवर्गीकृत हिस्से को इसके साथ परिचालन करने का निर्देश दिया जाता है।

सु. सामंत

(सुश्रुत सामंत)
उप सचिव, भारत सरकार
दूरभाष नं. 2309- 5244

प्रति

1. केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. उपाध्यक्ष, नीति आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली।
3. मंत्रिमंडल सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
4. भारत के राष्ट्रपति के सचिव, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
5. भारत के उपराष्ट्रपति के सचिव, 6, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली।
6. प्रधान मंत्री के प्रधान सचिव, पीएमओ, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली
7. अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, नई दिल्ली।
8. नीति आयोग के सभी सदस्य, योजना भवन, नई दिल्ली।
9. सचिव सभी मंत्रालयों/विभाग के सचिव, भारत सरकार, नई दिल्ली
10. वित्त राज्य मंत्री के निजी सचिव, वित्त सचिव के प्रधान निजी सचिव, सचिव (आर्थिक कार्य) के प्रधान निजी सचिव, सचिव (राजस्व) के प्रधान निजी सचिव, सचिव (व्यय) के प्रधान निजी सचिव, सचिव (डीआईपीएएम) के प्रधान निजी सचिव।
11. श्री वी. अनंत नागेश्वरन, मुख्य आर्थिक सलाहकार, आर्थिक कार्य विभाग।
12. अपर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
13. श्री मनोज सहाय, अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार (वित्त)।
14. सुश्री अपर्णा भाटिया, सलाहकार (प्रशासन/समन्वय/सी एंड सी)

15. सुश्री मनीषा सिन्हा, अपर सचिव (ओएमआई/क्रिप्टो आस्तिया और सीबीडीसी)
16. आर्थिक कार्य विभाग में सभी प्रभाग के प्रमुख। संयुक्त सचिव (आईपीपी/जेएस (आईएसडी) / संयुक्त सचिव (आईएनवी) / संयुक्त सचिव (बजट) संयुक्त सचिव (एफएम) /सभी सलाहकार/सीएएए
17. श्री राजेश मल्होत्रा, उप महानिदेशक (एम एंड सी), वित्त मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
18. गार्ड फाइल - 2023

ए-45011/04/2023-समन्वय.II

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

***

विषय: दिसंबर, **2023** माह के लिए आर्थिक कार्य विभाग (डीईए) से संबंधित महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों पर मासिक सारांश।

1. माह के दौरान लिए गए महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय और प्रमुख उपलब्धियां:

समष्टि आर्थिक अवलोकन:

भारतीय अर्थव्यवस्था के मजबूत विकास के कारण आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने दिसंबर में अपनी द्विमासिक बैठक के दौरान, रेपो रेट को अपरिवर्तित रखते हुए वित्तीय वर्ष 2023-24 (वित्तीय वर्ष 24) के लिए अपने पूर्वानुमान को 6.5 से बढ़ातक 7.0 प्रतिशत तक कर दिया गया है। दूसरी छमाही (एच2) में खपत, निवेश, विनिर्माण और निर्माण में मजबूत वृद्धि की उम्मीदों ने पूर्वानुमान के ऊपर की ओर संशोधन किया है।

नोमुरा, बार्कलेज और सिटीग्रुप जैसी वैश्विक एजेंसियों ने भी वित्त वर्ष 24 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था पर अपने पूर्वानुमान को बढ़ाकर 6.7 प्रतिशत कर दिया है। स्टैंडर्ड एंड पुअर (एस एंड पी) ने 6.4 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया है, साथ ही उम्मीद है कि वर्ष 2024-2026 के दौरान भारत की जीडीपी 6.4 और 7.0 के बीच बढ़ेगी। एसएंडपी का अनुमान है कि मजबूत घरेलू गतिविधि उच्च खाद्य मुद्रास्फीति और निर्यात में कमी से विपरीत परिस्थितियों की भरपाई (हेडविंड को ऑफसेट) करने की संभावना है। फिच रेटिंग्स ने बुनियादी ढांचे पर बढ़ते खर्च को देखते हुए अपने अनुमान को बढ़ाकर 6.9 प्रतिशत कर दिया है। यह आशा की जाती है कि सरकार आपूर्ति क्षेत्र में सुधार करेगी और प्रभावी कार्पोरेट और तुलन-पत्र से अधिकांश क्षेत्रों में पूंजीगत व्यय में बढ़ोतरी होगी। ।

सुदृढ़ विकास के साथ-साथ शीर्ष (हेडलाइन) मुद्रास्फीति में लगातार गिरावट आई है। बहरहाल , खाद्य मुद्रास्फीति चुनौतीपूर्ण बनी रही। खाद्य मुद्रास्फीति में वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए, सरकार ने देश में पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध को 31 मार्च 2024 तक बढ़ा दिया है। मसूर दाल पर आयात शुल्क छूट को भी 31 मार्च 2024 तक बढ़ा दिया गया है। ये उपाय अक्टूबर में उठाए गए पिछले कदमों को आगे बढ़ाते हुए जब सरकार ने प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के तहत लक्षित सब्सिडी को प्रति 14.2 किलोग्राम सिलेंडर पर 200 से बढ़ाकर 300 रुपये कर दिया था।

सरकार के पास अनाज की कीमतों में वृद्धि को रोकने के लिए बाजार में जारी करने के लिए पर्याप्त खाद्यान्न भंडार है। भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) ने वित्त वर्ष 24 में अब तक ओपन मार्केट सेल्स स्कीम (ओएमएसएस) के तहत 5.5 मिलियन टन गेहूं बेचा है. इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 24 में ओएमएसएस के तहत लगभग 12.5 मिलियन टन ऑफलोडिंग का इंतजार कर रहे हैं।

राजकोषीय मोर्चे पर सरकार मजबूत बनी रही। अप्रैल-नवंबर 2023 के दौरान शुद्ध कर संग्रह वर्ष-दर-वर्ष 17.2 प्रतिशत अधिक था। इस अवधि के दौरान पूंजीगत व्यय (वर्ष - दर-वर्ष) 48 प्रतिशत अधिक था, जो बजटीय परिव्यय को 58.5 प्रतिशत तक पहुंच गया। राजकोषीय घाटा लक्ष्य के भीतर समाहित होने की संभावना है क्योंकि यह वित्तीय वर्ष 24 के दो-तिहाई के पारित होने के बाद बजट राशि का केवल आधा है. **यह न केवल पिछले वर्ष की तुलना में बल्कि पिछले 5 वर्षों के औसत की तुलना में भी बेहतर प्रदर्शन है।**

बाह्य क्षेत्र भी तन्यक बना रहा। तिजारती माल घाटे (मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट) को कम करने और बढ़ती निवल सेवाओं की प्राप्तियों ने चालू खाता घाटे को वित्तीय वर्ष 24 के एच1 में जीडीपी के 1.0 प्रतिशत तक सीमित कर दिया, जो वित्तीय वर्ष 23 के एच1 में 2.9 प्रतिशत से कम है. अक्टूबर 2023 में भारत में एफडीआई प्रवाह 21 महीने के उच्च स्तर 5.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर पहुंच गया, जबकि पिछले छह महीनों के दौरान औसत प्रवाह केवल 0.76 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।

भारत ने संयुक्त अरब अमीरात से खरीदे गए कच्चे तेल के लिए रुपये में अपना पहला भुगतान भी किया (यूएई)। यह कदम भारतीय रिजर्व बैंक के सीमा पार भुगतान में रुपये की भूमिका को बढ़ावा देने, तेल आपूर्तिकर्ताओं में विविधता लाने और लेनदेन की लागत में कटौती करने के उद्देश्य के अनुरूप है।

कई देशों में मुद्रास्फीति में आई कमी के कारण विभिन्न केंद्रीय बैंकरों ने अपनी दरों में बढ़ोतरी को रोक दिया है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा दिसंबर 2023 में आयोजित अपनी नीतिगत बैठक में ब्याज दरों को 5.25-5.5 प्रतिशत की सीमा में अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया था। यूरोपीय सेंट्रल बैंक ने भी लगातार दूसरी बैठक के लिए ब्याज दरों को 4.5 प्रतिशत पर स्थिर रखा। इसके अलावा, बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी लगातार तीसरी बार अपनी दर वृद्धि को रोक दिया, जो 15 साल के उच्च स्तर 5.25 प्रतिशत पर पहुंच गया।

आर बी आई सहित प्रमुख केंद्रीय बैंकरों द्वारा दरों में वृद्धि को रोक दिया गया है, और विश्व भर में मुद्रास्फीति की दर नीचे आ गई है, वर्ष 2024 में नीतिगत दरों में तेज कमी की आशा है इससे वर्ष 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ-साथ अन्य कई अर्थव्यवस्थाओं की उत्पादन वृद्धि में तेजी आएगी।

2. महत्वपूर्ण घटनाक्रम:

(i) वित्त आयोग (विविध प्रावधान) अधिनियम 1951 (1951 का 33वां) के उपबंधों के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 280 के खंड (1) के अनुसरण में, **राष्ट्रपति ने** डॉ. अरविन्द पनगढ़िया, पूर्व उपाध्यक्ष, नीति आयोग और प्रोफेसर कोलम्बिया विश्विविद्यालय की अध्यक्षता में **सोलहवें वित्त आयोग का गठन किया।**

(ii) माननीय वित्त मंत्री ने, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के गर्वनर के रूप में, कोटे की **16 वीं आम समीक्षा के प्रस्तावित संकल्प के लिए मतपत्र** पर सकरात्मक स्वीकृति दी जिसमें उनके वर्तमान कोटा शेयरों (सभी 190 आईएमएफ सदस्यों के कोटे में समान आनुपातिक) के अनुपात में 50 प्रतिशत वृद्धि का प्रस्ताव हैं। भारत का कोटा अंशदान 13.11 बिलियन एसडीआर के वर्तमान स्तर से बढ़कर 19.57 करोड़ एसडीआर हो जाएगा (अर्थात एसडीआर 6,557.2 मिलियन की कुल कोटा वृद्धि) 15 दिसंबर 2023 को आईएमएफ के बोर्ड ऑफ गर्वनर ने इसे अनपाया।

(iii) माननीय वित्त मंत्री ने 20 दिसंबर, 2023 को नई दिल्ली में विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष से मुलाकत की। अवसंरचना के क्षमता निर्माण में सार्वजानिक और निजी क्षेत्रों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्पूवर्ण कदम में, **सार्वजनिक-निजी भागदारी शुरूआती ई-कोर्स** भी विश्व बैंक के अध्यक्ष द्वारा डीईएन सचिव, मुख्य आर्थक सलाहकार और परमेश्वरन अय्यर, कार्यकारी निदेशक (भारत) विश्व बैंक की उपस्थिति में 20 दिसंबर, 2023 को नई दिल्ली में शुरू किया गया था।

(iv) माननीय वित्त मंत्री ने नार्वे के व्यापार एवं उद्योग मंत्री तथा आर्थिक मामालों के लिए स्विस स्टेट सेक्रेटरी से भी मुलाकात की और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) व्यापार एवं आर्थिक भागीदारी करार (टीपीए) से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की।

(v) सरकारी स्तर पर निम्नलिखित महत्वपूर्ण बैठकें आयोजित की गई:

(क) 6, 7 दिसंबर, 2023 और 19 दिसंबर 203 को **भारत-यूके बीआईटी पर अनुवर्ती बैंठकें** (डीईए सचिव और यूके की डीजी ट्रेड सुश्री अमांडा ब्रुक्स के बीच) आयोजित की गई।

(ख) 11 से 12 दिसंबर 2023 तक **एनबीडी की कार्यकारी बोर्ड** की बैठक का 140 वां सत्र आयोजित किया गया।

(ग) 11 से 14 दिसंबर 2023 के दौरान **एआईआईबी निदेशक मंडल** की बोर्ड की बैठकें आयोजनों और रिट्रीट मीटिंग में वर्चुअल बैठक हुई।

(घ) ब्राजील के ब्रासीलिया में 13 से 15 दिसम्बर 2023 के दौरान जी **20 ब्राजीलियाई प्रेसीडेसी** के तहत पहली जी 20 संयुक्त शेरपा-वित्त और सेंट्रल बैंक डेप्युटीज बैंठक और पहली जी 20 वित्त और सेंट्रल बैंक डेप्युटीज मीटिंग आयोजित की गई। वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व मुख्य आर्थिक सलाहकार ने किया और भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व डिप्टी गवर्नर डॉ. माइकल पत्रा ने किया।

(ड.) **भारत-श्रीलंका बीआईटी वार्ताओं** का 12वां दौर वस्तुत: 13 दिसबंर 2023 को आयोजित किया गया।

(च) **भारत- सउदी अरब द्विपक्षीय निवेश संधि** (बीआईटी) वार्ता का छठा दौर 13 दिसबंर 2023 को डीवीसी के माध्यम से आयोजित किया गया।

(छ) **आईएफएडी की संसाधन समिति की बैठक की तेरहवीं पुन: पूर्ति** पर परामर्श का चौथा सत्र 14 से 15 दिसंबर 2023 तक आयोजित किया गया। बैठक में दूतावास के प्रतिनिधि व्यक्तिगत रूप से उपस्थित थे। भारत सरकार ने 2024-26 के दौरान आईएफएडी 13 पुन: पूर्ति चक्र के लिए 25 लाख अमरीकी डॉलर का योगदान दिया।

(ज) **आईपीडीएफ योजना** के तहत सहायता के प्रस्तावों पर विचार करने और उन्हें स्वीकृति देने के लिए निम्नलिखित हेतु दिसबंर 2023 में अनुमोदन समिति की तीन बैठकें आयोजित की गई:

(i) 4. 04 करोड़ रूपये तक के वित्तपोषण के साथ आईआईएम, मुंबई में छात्रों के लिए फिनटेक उत्कृष्टता केंद्र, आवास सुविधाओं के विकास के लिए संव्यवहार सलाहकार उपलब्ध/ नियोजित करना।

(ii) 4.80 करोड़ रूपये तक के वित्तपोषण के साथ अंडमान और निकोबार में इको-पर्यटन रिसॉर्टस के विकास के लिए टीएएस की खरीद/नियोजित करना।

(iii) 5 करोड़ रु तक के वित्तपोषण से द्वीप विकास प्राधिकरण (आईडीए), गृह मंत्रालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत द्वीपीय संघ राज्य क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए टीए उपलब्ध/ नियोजित करना।

(झ) भागीदार देशों को ऋण की तर्ज (एलओसी) पर अंतर-मंत्रालयी स्थायी समिति (आईएमएससी) की बैठक 28 दिसंबर, 2023 को हुई थी।

(ञ) सार्क विकास कोष (एसडीएफ) निदेशक मंडल की 36वीं बैठक 30 दिसंबर, 2023 को आयोजित की गई थी।

(ट) आईएमएफ-एसएआरटीटीएसी के चरण II के संचालन (जनवरी 2024-अप्रैल 2029) हेतु भारत सरकार द्वारा योगदान के लिए समझौता पत्र (एलयूओ) को अंतिम रूप दिया गया और हस्ताक्षर किए गए।

(vi) द्विपक्षीय और बहुपक्षीय विकास एजेंसियों के साथ निम्नलिखित ऋण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए:

(क) **एशियाई विकास बैंक** के साथ हस्ताक्षरित ऋण:

i. तन्यक (रैसिलिएन्ट) डब्ल्यूएसएस सेवाओं की विश्वसनीयता और दक्षता बढ़ाने के लिए उत्तराखंड एकीकृत और तन्यक शहरी विकास परियोजना को **125** मिलियन अमेरिकी डालर का अतिरिक्त वित्तपोषण;

ii. **100** मिलियन अमेरिकी डालर की त्रिपुरा शहरी और पर्यटन विकास परियोजना;

iii. **175** मिलियन अमेरिकी डालर की लागत से मध्य प्रदेश सड़क नेटवर्क की कनेक्टिविटी और लचीलापन बढ़ाना;

iv. **200** मिलियन अमेरिकी डालर की लागत से उत्तराखंड जलवायु अनुकूलन विद्युत प्रणाली विकास परियोजना;

v. पावर सेक्टर रिफॉर्म प्रोग्राम - **250** मिलियन अमरीकी डालर की लागत का उप-कार्यक्रम **1**;

vi. दिल्ली-मेरठ आरआरटीएस निवेश परियोजना – **250** मिलियन अमरीकी डालर के लिए **3** किश्त; और

vii. औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम – **250** मिलियन अमरीकी डालर के लिए उप-कार्यक्रम **2**।

(ख) आवासीय क्षेत्र के लिए रूफटॉप सौर कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त वित्तपोषण हेतु **विश्व बैंक** को **150** मिलियन अमेरिकी डालर के ऋण पर हस्ताक्षर किए गए।

(ग) **जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए)** के साथ हस्ताक्षरित ऋण:

i. 400 बिलियन जापानी येन के लिए मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल (वी) के निर्माण की परियोजना; और

ii. 15.301 बिलियन जापनी येन के लिए भारत में सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में जापान-भारत सहकारी कार्यों के लिए कार्यक्रम (चरण **2)**।

(घ) 100 मिलियन अमेरिकी डालर के ऋण के लिए मल्टी-मोडल और एकीकृत लॉजिस्टिक्स पारिस्थितिकी तंत्र कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए **ईडीसीएफ (कोरिया)** के साथ ऋण पर हस्ताक्षर किए गए।

(ङ) **जर्मन केएफडब्ल्यू** के साथ हस्ताक्षरित ऋण:

i. 100 मिलियन यूरो की लागत से ऋषिकेश एकीकृत शहरी अवसंरचना विकास (आईयूआईडी) कार्यक्रम चरण II (2 मिलियन यूरो के अनुदान सहित);

ii. इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन (सीआईटीआईआईएस) 2.0 कार्यक्रम के लिए 100 मिलियन यूरो के लिए सिटी इन्वेस्टमेंट;

iii. 500 मिलियन यूरो की बेंगलुरु उपनगरीय रेलवे परियोजना (के-आरआईडीई) (4.5 मिलियन यूरो के अनुदान के साथ);

iv. 200 मिलियन यूरो की जलवायु अनुकूलन ऊर्जा आपूर्ति कार्यक्रम (2 मिलियन यूरो के अनुदान के साथ);

v. 100 मिलियन यूरो की सतत शहरी विकास (जल/अपशिष्ट जल/एसडब्ल्यूएम) के लिए मुंबई क्षेत्रीय शहरी अवसंरचना सुधार कार्यक्रम (2.2 मिलियन यूरो के अनुदान के साथ); और

vi. महाजेनको के लिए 130 मिलियन यूरो की भारत-जर्मन सौर ऊर्जा भागीदारी III के तहत 245 मेगावाट सौर परियोजनाएं।

(च) 100 मिलियन यूरो हेतु नवाचार, एकीकृत और सतत (सीआईटीआईआईएस) 2.0 कार्यक्रम के लिए शहरी निवेश हेतु **फ्रेंच** एएफ़डी के साथ हस्ताक्षरित ऋण

(छ) **यूरोपीय निवेश बैंक** के साथ हस्ताक्षरित ऋण:

i. आगरा मेट्रो परियोजना – 200 मिलियन यूरो के लिए दूसरी किश्त; और

ii. कानपुर मेट्रो परियोजना - 300 मिलियन यूरो की तीसरी किश्त।

(vii) आर्थिक कार्य विभाग ने आईएमएफ बोर्ड के निम्नलिखित प्रमुख मामलों के लिए अनापत्ति / सहमति व्यक्त की:

(क) भारत के 2023 के अनुच्छेद IV के रिपोर्ट बंडल का प्रकाशन। रिपोर्ट 18 दिसंबर, 2023 को प्रकाशित हुई थी।

(ख) कोमोरोस को विस्तारित ऋण सुविधा के तहत पहली समीक्षा।

(ग) कांगो गणराज्य के लिए विस्तारित ऋण सुविधा के तहत चौथी समीक्षा।

(viii) इस महीने के दौरान निम्नलिखित **अधिसूचनाएं जारी की गईं:**

(क) सोलहवें वित्त आयोग का गठन।

(ख) डॉ. पंजाबराव देशमुख की 125वीं जयंती के अवसर पर ₹ 125/- मूल्यवर्ग का स्मारक सिक्का।

(ग) रामकृष्ण मिशन के 125 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ₹ 125/- मूल्यवर्ग का स्मारक सिक्का।

(घ) खरतरगाचा मिलेनियम के संस्थापक जैनाचार्य श्री जिनेश्वर सूरी के समारोह पर ₹ 1000/- मूल्यवर्ग का स्मारक सिक्का।

(ङ) डॉ. हरेकृष्ण महताब की 125वीं जयंती के अवसर पर ₹ 100/- मूल्यवर्ग का स्मारक सिक्का।

(च) कर्नाटक बैंक के शताब्दी समारोह के अवसर पर ₹ 100/- मूल्यवर्ग का स्मारक सिक्का।

3. न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन

सूचना प्रस्तुत करने में आईसीटी के उपयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

4. एसीसी के निर्देशों/आदेशों का गैर-अनुपालन: शून्य

5. माह के दौरान मंजूर किए गए एफडीआई प्रस्तावों का विवरण और विभाग में अनुमोदन की प्रतीक्षा वाले एफडीआई प्रस्तावों की स्थिति:

स्वीकृत प्रस्तावों की संख्या	:	04
विभाग में स्वीकृति की प्रतीक्षा में	:	11

6. **दिसंबर, 2023** के दौरान आर्थिक कार्य विभाग की स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा स्वीकृत बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं की संख्या: सात प्रस्ताव।

7. **दिसंबर, 2023** के दौरान स्वीकृत/अनुमोदित वीजीएफ परियोजनाओं की संख्या: शून्य

8. **दिसंबर, 2023** के दौरान स्वीकृत/अनुमोदित पीपीपीएसी परियोजनाओं की संख्या: शून्य।

9. **दिसंबर, 2023** के दौरान भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना (आईडीईएएस) के तहत अनुशंसित एलओसी:

क. पेट्रोलियम रिफाइनरी परियोजना के लिए मंगोलिया को 700 मिलियन अमेरिकी डालर का एलओसी; और

ख. गुयाना सरकार को 23.37 मिलियन अमेरिकी डालर का एलओसी। गुयाना को इस एलओसी को प्रायोगिक परियोजना के आधार पर ₹-मूल्यवर्गित एलओसी के रूप में नामित प्रदान करने के प्रयास किए गये है।